**Fourteenth Loksabha**

**Session : 8**
**Date : 02-08-2006**

**Participants : Kumar Shri Shailendra**

>

Title : Need to include Haridwar district in Uttar Pradesh.

**श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल)** : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विाय रखना चाहता हूं। जनपद हरिद्वार को उत्तरांचल से अलग कर पुनः उत्तर प्रदेश में शामिल किया जाए। कल हरिद्वार के 10000 लोगों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, जिसमें हमारी पार्टी के लीडर प्रो. राम गोपाल जी, राजनारायण बुधौलिया जी, प्रो. बघेल और मैं स्वयं था। संविधान की धारा 3 के अंतर्गत महामहिम राट्रपति जी द्वारा उत्तर प्रदेश जिला पुनर्गठन विधेयक 2000 में विचारार्थ विधान मंडल को भेजा गया था जिसको उत्तर प्रदेश विधान मंडल ने दो बार पास कर केन्द्र सरकार को भेजा, जिसमें संपूर्ण जनपद हरिद्वार को उत्तर प्रदेश में ही रखने का संकल्प व्यक्त किया गया था। केन्द्र सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये से हरिद्वार को जान-बूझकर उत्तरांचल में शामिल किया गया जिसमें खासकर दोाी भाजपा के तत्कालीन मंत्री* इसके जिम्मेदार कांग्रेस के लोग भी हैं।

---

*Expunged as ordered by the Chair.

**उपाध्यक्ष महोदय** : वह हाउस के मैम्बर नहीं हैं। उनका नाम एक्सपंज कर दीजिए।

**श्री शैलेन्द्र कुमार** : हरिद्वार के 15 लाख नौजवान - किसान, व्यापारी, अल्पसंख्यक, ट्रांसपोर्टर, वकील और अध्यापकों की इच्छाओं और आकांक्षाओं पर कुठाराघात किया गया है। लोग सड़कों पर उतरे और पुलिस ने उन पर गोलियां भी चलाईं जिसमें एक किसान रघुबीर की मौत भी हो गई। यही नहीं, हजारों लोगों को जेल भेजा गया और विभिन्न धाराओं में मुकदमे चलाकर आतंकित और प्रताड़ित करने की कार्रवाई उत्तरांचल की सरकार कर रही है। वहां व्यवसाय के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है। व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के दोहरे टैक्स की मार झेलनी पड़ रही है। न्यायालयों में अधिकारी न होने के कारण वहां लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ...(व्यवधान) अल्पसंख्यकों और दलितों की उपेक्षा हो रही है और उनके साथ अन्याय हो रहा है। पिछड़ों का आरक्षण 27 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत और दलितों का 19 प्रतिशत कर दिया गया है। भूमि कानूनों के जरिये किसानों को गुलाम बनाकर रखा गया है। 12 में से 11 विधान सभाओं को परिसीमन में जोड़ा गया और 2004 में पुनः विधान सभा में प्रस्ताव पास कर केन्द्र सरकार को भेजा गया है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि हरिद्वार, जो उत्तरांचल में है, वहां के 15 लाख लोगों की जन आकांक्षाओं को देखते हुए और जो कल 10000 लोगों की भीड़ यहां आई थी, उनकी भावनाओं को देखते हुए उसे पुनः उत्तर प्रदेश में शामिल किया जाए। ...(व्यवधान)